भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था: एक प्रश्न

साभार: फाइनेंसियल एक्सप्रेस
(03 नवंबर, 2017)

मदन सबनवीस
(संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

हालांकि, सभी तथ्य इससे जुड़े हुए है कि भारत लंबे समय से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन फिर भी आईएफपीआरआई और विश्व बैंक दोनों के हालिया रिपोर्ट इस तथ्य के विपरीत चित्र दिखाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) और विश्व बैंक द्वारा इस महीने प्रकाशित की गई दो महत्वपूर्ण वैश्विक रिपोर्ट भारत के सन्दर्भ में दो अलग-अलग आर्थिक फ्रेम पेश करती हैं। विश्व बैंक की 'डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' मुख्य रूप से व्यापार करने पर केंद्रित है, जो अनिवार्य रूप से एक प्रतिबिंब है कि सरकारें लालफीताशाही को कम करने और व्यापार करने के लिए इसे और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए क्या-क्या करती हैं और क्या-क्या कर रही है। यह सिर्फ एक व्यवसाय शुरू करने के मामले से सम्बंधित नहीं है बल्कि यह श्रेय, क्रेडिट, बाजार, व्यापार, दिवालियापन आदि के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। आईएफपीआरआई की वैश्विक भूख रिपोर्ट, जो समाजवाद की ओर झुकाव वाले सामाजिक चिंताओ को, सापेक्ष अभाव के स्तर को और इसको कम करने में सरकार की जिम्मेदारी पर प्रकाश डालता है। सरकार को उन सभी पहलुओं पर कार्य करनी चाहिए जो व्यापार करने को सुगम बनाये। हांलाकि, 30 रैंकों में सुधार सरकार द्वारा इस ओर किये प्रयास को सही साबित करती है। हमेशा से 'डूइंग बिजनेस' में कम रैंक व्यापारिक स्तर पर बहुपक्षीय एजेंसियों और रेटिंग कंपनियों के लिए एक चिंता का विषय रहा है, जहां कम रैंक का अक्सर पॉलिसी ढांचे के लिए एक कारण के रूप में उपयोग किया जाता है। दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) में व्याप्त कमी पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने से निवेशक भारत में निवेश करने के बारे में ज्यादा आश्वस्त हो रहे हैं।

विश्व बैंक ने स्वीकार किया है कि इस अभ्यास में जीएसटी शामिल नहीं किया गया है, जिसका मतलब है कि आगे बढ़कर, रैंक में और तेजी से सुधार होगा, क्योंकि को हमेशा से कर-निर्धारण एक बड़ी चिंता रही है, जहां संरचना बहुत जटिल थी करों और दरों ने गंभीर मुद्दों को जन्म दिया है। यह देखते हुए कि, एक वर्ष के समय में, बाधाएं पार हो गई होंगी, लेकिन इसके विपरीत परिणाम भारत के पक्ष में नहीं है। यही हाल दिवालियापन के लिए भी है, जहां आईबीसी का कार्यान्वयन कमजोर साबित हुआ। वास्तव में, पुनर्पूंजीकरण की कवायद पर और अधिक स्पष्टता भी होगी जो कि अगली तिमाही में या तो किसी भी समय शुरू होनी चाहिए। इसलिए, शीर्ष 50 देशों में आने का सपना आज यथार्थवादी दिखता है और ये कुछ ऐसा है जिससे हम खुश रह सकते हैं।

यह अपेक्षाकृत भी यथार्थवादी होगा कि वैश्विक रेटिंग कंपनियां देश की रेटिंग की समीक्षा करें और कम से कम 2 अंक के उन्नयन पर गंभीरता से विचार करें। वास्तव में, मजबूत आर्थिक संख्याएं, जिनमें सरकारी वित्त, विनिमय दर, विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी निवेश आदि शामिल हैं, उन्हें उन्नयन के लिए मजबूत होना चाहिए। रैंकिंग के संदर्भ में कुछ बड़ी सफलता मिली है जो बाजारों में अल्पसंख्यक रुचियों (रैंक 4) की सुरक्षा के क्षेत्रों में और ऋण प्राप्त करने (रैंक 29) है, जहां नियामकों सेबी और आरबीआई हमेशा सक्रिय रहा है। कर मोर्चे पर सुधार भी प्रगतिशील रहे हैं, 172 से 119 तक के रैंक में सुधार हुआ है। जीएसटी को हमें निश्चित तौर पर पैमाने पर आगे बढ़ाना चाहिए।

उन क्षेत्रों में जहां गिरावट रही है या जहां सीमित प्रगति देखी गई है, उसमें व्यापार शुरू करने में, निर्माण परमिट, संपत्ति की रजिस्ट्री और सीमाओं के पार व्यापार शामिल है। पहले तीनों के लिए, गेंद वास्तव में राज्यों और स्थानीय प्राधिकरणों के पाले में है, जहां केंद्र सीमित रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। इसलिए राज्यों को इन पहलुओं पर काम करना पड़ेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे भी राज्य रैंकिंग सुधार के लिए तत्पर है (वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एक अलग रिपोर्ट पेश की गई है)। यहाँ एक सवाल यह है कि यह निवेश से कैसे जुड़ा हुआ है? उत्तर यह है कि निर्णय लेने के लिए रैंक ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा, बल्कि स्थिति को और महत्वपूर्ण बनाया जाना चाहिए, जिससे इसमें सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा। जैसा कि नीति तैयार करने और सुधार एक सतत प्रक्रिया है, परिवर्तन किए गए फैसले को प्रभावित करना होगा, घरेलू निवेशक सकारात्मक रूप से कर सुधारों पर ध्यान देंगे या कोई व्यवसाय स्थापित करने के लिए लागू किये गये किसी भी उपाय को विशेष रूप से जहां भूमि, निर्माण आदि का संबंध है। जहां निवेश करना है, यह निर्धारित करते समय विदेशी निवेशक इस पैमाने पर नियमित रूप से स्कोर को देखते हैं, क्योंकि विश्व बैंक रैंकिंग सार्वभौमिक रूप से निष्पक्ष है। इसलिए, सुधारों की गति को तेज करने के लिए दिखाए गए निर्धारण के साथ यह उम्मीद की जा सकती है कि निवेश के प्रवाह में वृद्धि होगी, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां लालफीताशाही और नौकरशाही प्रक्रियाएं मार्ग में अवरोधक बन कर खड़े हैं।

आईएफपीआरआई हंगर इंडेक्स रिपोर्ट हालांकि, निराशाजनक है और यह इस तथ्य का एक प्रतिबिंब है कि पिछले दशक में हासिल विकास में एक संभ्रांतवादी झुकाव है और उत्पादक क्षेत्रों पर संकीर्ण भारी फोकस ने अपने तरीके से काम करने वाले ट्रिकल-डाउन प्रभावों (ट्रिकल-डाउन प्रभाव विपणन में उत्पाद अपनाने का एक मॉडल है जो कई उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं को प्रभावित करता है, यह बताता है कि फैशन ऊपरी वर्गों से समाज के भीतर निचले वर्गों तक जाती है, जहाँ प्रत्येक सामाजिक वर्ग एक उच्च सामाजिक वर्ग से प्रभावित होता है।) के बिना लक्ष्य हासिल किया है। वास्तव में, एक कुशल पुनर्वित्त की बजाय सरकार को एक उत्पादक संवितरक बनने पर निरंतर ध्यान केन्द्रित करना गरीबों के लिए ठोस वितरण तंत्र बनाता है, जिसे अभी देखा जाना बाकी है। यह स्कोर 1992 और 2000 के बीच 46.2 से 38.2 के बीच तेजी से नीचे चला गया, फिर अगले आठ वर्षों में 35.6, यानी 2.6 पर नीचे चला गया, उसके बाद अगले आठ वर्षों में 3.2 से 31.4 के बीच, जो यह दर्शाता है कि गरीबों के कल्याण पर प्रत्यक्ष ध्यान देने की तुलना में पिछले दशक

में रणनीति तेजी से बढ़ रही थी। 14.5% जनसंख्या को कुपोषित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, 21% बच्चों में कुपोषण की समस्या (ऊँचाई की तुलना में कम वजन) और 38.4% बच्चों को अवरुद्ध (उम्र के सापेक्ष ऊँचाई) देखी गयी है, जो राज्य की विफलता को दर्शाता है। एक समतावादी समाज के बढ़ने की दृष्टि से ऐसी संख्याएं उपेक्षा को प्रतिबिंबित करती हैं, जबकि आर्थिक दृष्टिकोण से, ऐसे आंकड़े तथाकथित जनसांख्यिकीय लाभांश के बारे में नहीं बोलते हैं, जो हम कहते हैं।

काफी स्पष्ट रूप से गरीबों की उपेक्षा के दशकों में ये संख्या में परिलक्षित होता है और जब केंद्र सरकार और समाज कल्याण पर व्यय का आलोचना करने के लिए फैशनेबल हो गया है, तो रणनीतियों को न केवल पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है, बल्कि सार्थक तरीके से आवंटन को भी बढ़ाना हैं। अन्यथा, ऐसा एकतरफा विकास स्थायी नहीं होगा। विडंबना यह है कि भारत दोनों सूचकांकों में 100वें स्थान पर है, जहां पर कारोबार बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ 190 देशों के एक समूह में 30 रैंकों में सुधार हुआ है। भूख सूचक सूचकांक 119 देशों के लिए है और इसलिए ये संख्याओं में से प्रत्येक के लिए भावनाओं की श्रेणी अलग है। वास्तव में, हंगरी सूचकांक में भारत को बांग्लादेश और श्रीलंका की तुलना में कम क्रम में रखा गया है। जबकि तथ्य से जुड़ा हुआ है कि भारत लंबे समय से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन फिर भी आईएफपीआरआई और विश्व बैंक दोनों के हालिया रिपोर्ट इस तथ्य के विपरीत चित्र दिखाते हैं। जिन सवालों को हम पूछ सकते हैं वे यह हैं कि एक ऐसा देश जिसने ऐसे सुधारों को देखा है, केवल 7% तक कैसे बढ़ सकता है? इसी सन्दर्भ में, यह सवाल भी सामने आता है कि 7% से बढ़ने वाले देश में इतने उच्च स्तर का अभाव क्यों है?

संबंधित तथ्य

ग्लोबल हंगर इंडेक्स?

- ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भुखमरी को मापने का एक पैमाना है जो वैश्विक, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर भुखमरी को प्रदर्शित करता है।
- उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (International Food Policy Research Institute& IFPRI) द्वारा प्रतिवर्ष जारी किये जाने वाले इस इंडेक्स में उन देशों को शामिल नहीं किया जाता है जो विकास के एक ऐसे स्तर तक पहुँच चुके हैं, जहाँ भुखमरी नगण्य मात्रा में है।
- इंडेक्स में शामिल न किये जाने वाले देशों में पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश अमेरिका, कनाडा इत्यादि शामिल हैं। साथ ही कुछ ऐसे अल्प विकसित देश भी इस इंडेक्स से बाहर रहते हैं जिनके भुखमरी संबंधी आँकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते या अपर्याप्त होते हैं, जैसे बुरूंडी, इरीट्रिया, लीबिया, सूडान, सोमालिया आदि।

आवश्यकता?

- 1990 के दशक से वैश्विक अर्थव्यवस्था का स्वरूप तेजी से बदलने लगा था। मुक्त बाजारों को आर्थिक विकास का वाहक माना जाने लगा था और लगभग सभी राष्ट्र अपने-अपने बाजारों को मुक्त करने लगे। एक ओर जहाँ समृद्धि बढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी ओर वैश्विक जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपने लिये दो वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पा रहा था।
- कई अन्य समस्याओं के अलावा भुखमरी भी इसी वैश्वीकरण की एक बाईप्रोडक्ट थी और इस समस्या के समाधान के लिये आवश्यक था कि भुखमरी आदि से संबंधित आँकड़े सुस्पष्ट हों, ताकि इनका विश्लेषण कर यह ज्ञात किया जा सके कि अलग-अलग देशों व क्षेत्रों में भुखमरी की क्या स्थिति है।
- यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष इसके आँकड़े प्रकाशित किये जाते हैं, ताकि नीतियाँ अधिक जनोन्मुखी हो सकें। विदित हो कि वर्ष 2006 में सबसे पहले 'वेल्ट हंगरलाइफ' नाम के एक जर्मन स्वयंसेवी संगठन ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी की थी।
- इस इंडेक्स का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि इसके प्रदत्त स्कोर के माध्यम से विभिन्न देश अन्य देशों से या स्वयं के पिछले वर्ष के आँकड़ों से भुखमरी की स्थिति का तुलनात्मक मूल्यांकन कर इससे निपटने की दिशा में प्रयास करें।
- भुखमरी के मापन के लिये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान चार आधारों (आबादी में कुपोषणग्रस्त लोगों की संख्या, बाल मृत्यु दर, अल्प विकसित बच्चों की संख्या और अपनी उम्र की तुलना में छोटे कद और कम वजन वाले बच्चों की तादाद) को चुनता है और उनके आनुपातिक मूल्यों का समेकन कर इंडेक्स जारी करता है। इनमें से अल्प पोषण तथा बाल मृत्यु दर को ज्यादा महत्त्व दिया जाता है।

वर्तमान रिपोर्ट?

- अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के अनुसार 119 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 100वें पायदान पर है और वह उत्तर कोरिया और बांग्लादेश जैसे देशों से भी पीछे है।
- दरअसल, पिछले साल भारत इस इंडेक्स में 97वें स्थान पर था और अब 100वें स्थान पर है। यानी इस साल वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत 3 स्थान और पीछे चला गया है।
- एशिया में एक बड़ी शक्ति के तौर पर पहचान रखने वाला भारत समूचे एशिया में सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आगे है जबकि नेपाल, म्याँमार, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी पीछे है।
- रिपोर्ट के मुताबिक भारत, चीन (29), नेपाल (72), म्याँमार (77), श्रीलंका (84) और बांग्लादेश (88) से पीछे है।
- हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे धनवान व्यक्तियों की सूची में यह दिखा था कि देश के सबसे धनवान व्यक्ति एवं समूहों की संपत्ति में पिछले साल के मुकाबले काफी वृद्धि हुई है। एक ओर तो धनवान और भी धनवान बनते जा रहे हैं, जबकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत नीचे खिसकता जा रहा है।

संभावित प्रश्न

वैश्विक महाशक्ति बनने की राह पर आगे बढ़ रहे भारत के लिये हाल ही में 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स' की रिपोर्ट चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। वर्तमान रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इस क्षेत्र में क्या आपेक्षित सुधार किये जाने चाहिये? चर्चा कीजिये। (200 शब्द)

Recently, the report of 'Global Hunger Index' for India going forward on becoming a global superpower gives a worrying picture. Keeping the current report in mind, what should be done by the government in this area? Discuss. (200 words)